भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में बृहस्पतिवार तिथि २ सितम्बर, १९५४ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

RELIEF TO THE PENSIONERS.

*52. **Shri HARIBANSH SAHAY** : Will the Minister in charge of the Finance Department be pleased to state—

(*a*) why the relief to the pensioners recommended by the "Pay Revision Committee" as noted in paragraph 60 of the Committee's report has not yet been given effect to;

(*b*) what consideration has been shown to the pensioners as suggested in paragraph 89 of the above Committee's report;

(*c*) whether Government have taken into consideration the fact that the price of foodgrains prevailing at present has abnormally risen and Government pensioners are left practically to live as destitute;

(*d*) whether in view of the above circumstances and in their capacity as employer, Government even now propose to take immediate steps to ameliorate the condition of the poor pensioners who are facing starvation in the present unprecedented days of hardship?

Dr. ANUGRAH NARAYAN SINHA : (*a*) The recommendation of the Pay Revision Committee in para. 60 of their report, was duly considered by Government, and was, as in many other cases, accepted by Government with modifications. The recommendation as accepted by Government has already been given effect to in Government Order no. 3536-F., dated the 19th March, 1948, a copy of which is placed on the table.

(*b*) The recommendation of the Pay Revision Committee was considered and accepted by Government. Orders were issued in F. D. resolution no. FPAR-12/50—12548F, dated the 23rd August, 1950, a copy of which is placed on the table.

(*c*) The relief extended to pensioners has been sanctioned after due consideration of the high prices. The temporary increase allowed by the State Government is higher than that granted by the Government of India.

(*d*) As stated in reply to clause (*a*) above, relief to the pensioners has already been sanctioned by Government in Government Order no.

श्री राम लखन सिंह यादव—अगर करीब करीब दो महीने नोमिनेट किये हुए हों गये तो क्या मेम्बरों द्वारा इस पर कोई आपत्ति की गई या कोई आलोचना की गई?

श्री भोला पासवान—अध्यक्ष महोदय, इतना डिटेल में क्या सवाल पूछा जा सकता है?

अध्यक्ष—आपको जितनी बातें मालूम हों उनका जवाब दें और जो नहीं मालम हैं उनकी सूचना मांगें। अपने अन्दाज से सवाल का जवाब नहीं दें।

श्री भोला पासवान—मैं अन्दाज से जवाब नहीं दे रहा हू। मैं यही जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न कैसे उठता है।

श्री रंगबहादुर प्रसाद—सरकार को यह मालूम है कि नहीं कि जब चुनाव की तिथि २६ रखी गयी थी तो उस तारीख को चुनाव नहीं करके ४ जुलाई निश्चित की गयी लेकिन बाद में उसको भी रोक दिया गया? तो मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया?

श्री भोला पासवान—किसने चुनाव रोक दिया इसका हवाला दें।

जिला परिषदों का चुनाव।

*७९। श्री राम सुन्दर तिवारी—क्या मंत्री, स्वायत्त-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) बिहार राज्य के उन डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव जिनका समय निश्चित अवधि से अधिक हो गया है, १९५४-५५ में कराने का क्या सरकार ने निश्चय किया है, या नहीं;

(ख) क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार इस बात को गंभीरतापूर्वक सोच रही है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भंग कर दिया जाय?

श्री भोला पासवान—(क) सरकार ने निश्चय किया है कि कुछ जिला बोर्डों का चुनाव १९५४-५५ में हो और कुछ जिला बोर्डों का चुनाव उसके बाद हो।

(ख) उत्तर नकारात्मक है।

श्री रामसुन्दर तिवारी—क्या सरकार बतलायेगी कि कितने जिला बोर्डों का चुनाव १९५४-५५ में हो जायेगा?

श्री भोला पासवान—इसकी पृथक सूचना चाहिए।

श्री रामसुन्दर तिवारी—मैं जानना चाहता हूं कि जिन जिला बोर्डों का चुनाव १९५४-५५ में होने जा रहा है, वह किस आधार पर होने जा रहा है?

अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर तिवारी—क्या सरकार ने कोई कमिटी बनायी है जिसने जिला बोर्डों को भंग करने की राय दी?

श्री भोला पासवान—यह सवाल कैसे उठता है।

श्री कर्पूरी ठाकुर—सरकार ने कहा है कि कुछ चुनाव १९५४-५५ में होंगे और कुछ बाद में तो मैं जानना चाहता हूं कि बाद की अवधि क्या होगी?

अध्यक्ष—आप जो अर्थ लगावें।

श्री कर्पूरी ठाकुर—माननीय मंत्री जवाब दें कि बाद का क्या अर्थ है?

श्री भोला पासवान—पिछले सेशन में एक सवाल का जवाब दिया गया था कि १९५४-५५ में सब का चुनाव हो जायगा।

श्री कर्पूरी ठाकुर—माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि आज का जो जवाब है वह सही है या पिछला जवाब सही है?

अध्यक्ष—माननीय मंत्री का कहना है कि कुछ बोर्डों का चुनाव निश्चित हो चुका है और जिनका नहीं निश्चित हुआ है उनका बाद में हो सकता है।

श्री हरिहर प्रसाद सिंह—क्या माननीय मंत्री का ध्यान उस खबर की ओर गया है कि जो इस राज्य सरकार के एक मंत्री ने अपने बयान में दिया है कि सरकार विचार कर रही है कि जिला बोर्डों को हटा दिया जाय?

अध्यक्ष—यह अलग प्रश्न है। इसकी अलग सूचना दीजिए।

श्री पशुपति सिंह—सरकार ने जवाब में कहा है कि कुछ जिला बोर्डों के चुनाव के संबंध में निश्चय हो चुका है और कुछ का बाकी है तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन जिला बोर्डों का निश्चय १९५४-५५ के लिए हो गया है उसका आधार क्या है और जिनका नहीं हुआ है उनका क्या आधार है?

अध्यक्ष—आधार के बारे में एक प्रश्न को हमने नामंजूर कर दिया है।

श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल—जिन जिला बोर्डों का समय बीत चुका है उन सभी का चुनाव एक साथ सरकार क्यों नहीं करने जा रही है?

श्री भोला पासवान—इस संबंध में बताया गया है कि कुछ जिला बोर्डों का चुनाव १९५४-५५ में होगा और कुछ का बाद में होगा। इसका कारण बहुत कुछ हो सकता है। आर्थिक कठिनाई भी एक कारण है और डिटेल में जानना चाहेंगे तो मैं बयान कर दूंगा।

SUPPLY OF WATER TO JHARIA TOWN.

*80. **Shri PURSHOTTAM CHOUHAN**: Will the Minister in-charge of the Local Self-Government Department be pleased to stat—

(*a*) whether it is a fact that a meeting of the citizens of Jharia Coalfield was held on the 13th May, 1954 to draw the attention of the Government and the Jharia Water Board towards the continued scarcity of water in the Jharia Coalfield;

(*b*) whether it is a fact that resolutions were passed at the above meeting protesting against the unprecedented increased rates for water by the Jharia Water Board;

(*c*) whether it is a fact that copies of those resolutions passed in the above meeting were sent to the Government by the Secretary, Jharia Town Citizen Welfare Association;

(*d*) if the answer to clauses (*a*), (*b*) and (*c*) be in the affirmative, what steps Government have taken to redress the grievances?

Shri BHOLA PASWAN: (*a*), (*b*) and (*c*) are in the affirmative.

(*d*) All possible steps are being taken to remove the water scarcity. In view of the limited quantity of drinking water available with the Board and ever-increasing demand for greater supply the Board had to take recourse to conserve the supply of wholesome and pure drinking water and limit the consumption by large consumers. With this end in view and with the sanction of Government, the Board has placed the rate of water-supply on a sliding scale with effect from the 1st April, 1954. This has not been introduced for profit and as and when the situation will improve, the position will be reviewed and the rates modified. The proposal for creation of a Municipality at Jharia is engaging the attention of Government.

Shri PURUSHOTTAM CHOUHAN: May I know whether there is a scheme for supplying water to Jharia is under the consideration of Government at present?

Shri BHOLA PASWAN: The answer is in the affirmative.